सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-2 22 जनवरी से 5 फरवरी, 2014 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

कॉमरेड लेनिन जिन्दाबाद

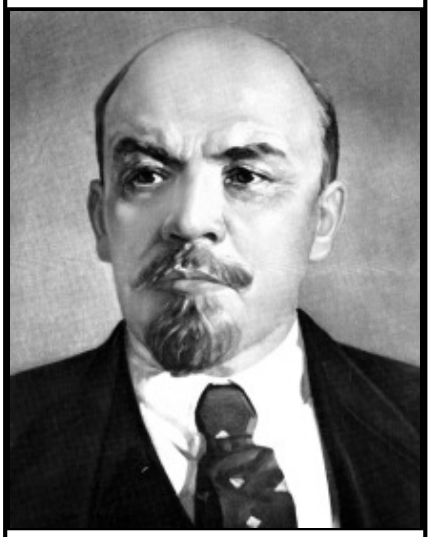

22 अप्रैल 1870 - 21 जनवरी 1924

''बुर्जुआ अर्थशास्त्री इस संकट को मात्र 'अशान्ति' के रूप में चित्रित करते हैं..... दूसरी तरफ क्रान्तिकारी कभी-कभी यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह संकट नितांत निराशाजनक है। यह एक गलती है। नितांत निराशाजनक जैसी कोई चीज नहीं होती है। बुर्जुआ वर्ग एक अक्खड़ लुटेरे जैसा आचरण करता है जिसका दिमाग खराब हो गया हो; यह मूर्खता पर मूर्खता करता है, स्थिति को और भी बदतर बना देता है और अपने खुद के विनाश को तीव्रतर करता है। यह सब सच है। लेकिन यह 'साबित' नहीं किया जा सकता है कि इसके द्वारा शोषितों की एक अल्पसंख्या को किसी तरह की कुछ छोटी-मोटी रियायतें देकर बेवकूफ बनाने का या एक आन्दोलन को या किसी तबके की या अन्य शोषित-पीड़ितों की बगावत को कुचलने का कोई मौका ही नहीं है। पहले से ही यह 'साबित' करने की कोशिश करना कि स्थिति 'नितांत' निराशाजनक है कोरा पण्डिताऊपन होगा या अवधारणाओं और लोकलुभावने जुमलों की बाजीगरी होगी। दुनिया भर में बुर्जुआ व्यवस्था अति गंभीर क्रान्तिकारी संकट से रूबरू है। क्रान्तिकारी पार्टियों को अपनी व्यावहारिक कार्रवाइयों के जरिए अब 'साबित' करना चाहिए कि पर्याप्त रूप से इस संकट को एक सफल और विजयी क्रान्ति की खातिर इस्तेमाल करने के लिए वे पर्याप्त बुद्धिमान और संगठित हैं, शोषित जनता के सम्पर्क में हैं, पर्याप्त दृढ़निश्चयी और निपुण हैं।'' –लेनिन

(रिपोर्ट ऑन दी इण्टरनेशनल सिच्युएशन एण्ड दि फण्डामेण्टल टास्क्स ऑफ दी कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल, सी.डब्ल्यू. वोल. XXV पेज 340-41)

जनविरोधी विधान परिषद के खिलाफ एसयूसीआई(सी) द्वारा आहूत आसाम बंध को मिला भारी समर्थन

3 जनवरी को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा आहूत 12 घण्टे के आसाम बंध को यहां के लोगों ने स्वत:स्फूर्त समर्थन दिया। समर्थन कई मायने में अनोखा और महत्वपूर्ण था। एसयूसीआई (सी) द्वारा आसाम की कांग्रेसी सरकार के उस फैसले के खिलाफ बंध का आह्वान अकेले अपने दम पर किया गया था जिसमें आसाम के लोगों पर बिल्कुल गैर जरूरी विधान परिषद या विधान सभा के तथाकथित उपरि सदन को थोपा जा रहा था। इसका गठन मनोनीत सदस्यों से होगा, उन्हें चुनी गई विधान सभा के सदस्यों के समान विधायकों का दर्जा प्राप्त होगा। ऐसी एक विधान परिषद के गठन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने का भारी दुरुपयोग होगा जो शासक पार्टी से प्रतिबद्धता रखने वाले मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों द्वारा इस 'उपरि सदन' की अवधारणा को लागू किया गया था। इसका मकसद था भारतीय नेताओं को बिना चुनावों का सामना किये ही सत्ता का स्वाद लेने दिया जाये ताकि उन्हें अपनी तरफ खींचा जा सके और भारत के आजादी आन्दोलन को कमजोर किया जा सके। आजाद भारत में शासक पार्टियों ने इसे अपनी पसंद के कुछ लोगों को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

छात्रा से गैंगरेप के दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग पर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन

दिल्ली : कलकत्ता में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ दो बार बलात्कार करने के बाद जलाकर हत्या कर डालने की नृशंस घटना के खिलाफ ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, एआईडीएसओ और एआईडीवाईओ के कार्यकर्ताओं ने 8 जनवरी को दिल्ली में बंग भवन के समक्ष एक विरोध प्रदर्शन किया तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।

वहां हुई सभा को ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड रितु कौशिक, ए.आई.डी.वाई.ओ. की राज्य सचिव कॉमरेड प्रकाश देवी, ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रशान्त कुमार और एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि आज देशभर में हर राज्य में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, महिलाओं व छात्राओं पर अपराध-अत्याचार बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सभी राज्यों में राजनीतिक संरक्षण में अपराधी तत्वों के हौंसले अत्यधिक बढ़ गये हैं और वे किसी भी प्रकार का अपराध बेखौफ कर गुजरते हैं। पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत के कारण अपराधी जुर्म की सजा से साफ बच निकलते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कलकत्ता में 16 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले दरिंदों को मौत की सजा दिए जाने और दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों का अहम कारक प्रचार माध्यमों से परोसी जा रही अश्लीलता व हिंसा और धड़ल्ले से जारी नशाखोरी पर भी रोक लगाने की मांग की।

पटना : कोलकाता में शांभवी के साथ दो-दो बार गैंगरेप व उसकी निर्मम हत्या के खिलाफ ऑल इंडिया डीएसओ, ऑल इंडिया डीवाईओ तथा ऑल इंडिया एम एस एस के संयुक्त तत्वावधान में भगत सिंह चौक से विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च भगत सिंह चौक से पटना जंक्शन गोलंबर पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया डीएसओ के प्रांतीय

(शेष पृष्ठ 8 पर)

आशा वर्करों ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन

दिल्ली : आशा वर्कर्स की समस्याओं के समाधान व अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन निरन्तर प्रयासरत है। इसी कड़ी में एसोसिएशन की तरफ से 6 जनवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल से उनके कौशाम्बी स्थित आवास पर भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया व ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाने व उनकी सेवाओं को नियमित किया जाने, प्रोत्साहन राशि के बजाय समुचित वेतन दिया जाने जो 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो कि वर्तमान में 20000 रुपए मासिक से अधिक बनता है, आगंनबाड़ी वर्करों के समान मानदेय देने, टीकाकरण व अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि तुरन्त दोगुना करने और इसमें हर वर्ष वृद्धि करने, इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल करने और इसमें अकारण कोई कटौती न की जाने, यात्रा भत्ता प्रति माह कम से कम 1500 रुपए देने; कापी, स्टेशनरी, मोबाइल व सर्दी-गर्मी की वर्दी का खर्चा देने, आशा के कार्य निष्पादन व प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए यदि कुछ नए नियम बनाए जाते हैं तो ऐसे परिवर्तनों को लागू करने से एक माह पहले इसकी पूरी जानकारी दी जाने की मांग की।

इसके अलावा 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आशा वर्कर को ट्रेनिंग देकर एएनएम बनाया जाने, समय बर्बाद न हो और वे अपना कार्य इज्जत के साथ पूर्ण कर सके इसके लिए सभी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में 'आशा' के लिए अलग काउण्टर, आशा रूम आदि बनाने की व्यवस्था करने, मातृत्व लाभ प्रदान करने, आशा कर्मियों के बी.पी.एल. कार्ड बनाने, भविष्य की सुरक्षा के मद्देनजर आशा वर्करों को पेंशन, स्वास्थ्य व जीवन बीमा कवर के सेवा लाभ दिये जाने और आशा वर्कर को मनमर्जी से हटाना व परेशान करना बंद करने की भी मांग की गई।

प्रतिनिधिमण्डल में सलाहकार हरीश त्यागी, अध्यक्ष एम. चौरसिया, उपाध्यक्ष सविता, सचिव रेणु एवं फरीदा, सहसचिव कनुप्रिया एवं कार्यकारिणी सदस्य सुशीला, मधु, सुषमा, विजयलक्ष्मी व रीता शामिल थे।

एआईडीएसओ ने की नि:शुल्क बस पास की मांग

रोहतक (हरियाणा): छात्र संगठन ऑल इण्डिया डीएसओ का एक प्रतिनिधिमंण्डल 13 जनवरी को रोहतक के जिला महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज और उपायुक्त से मिला और दोनों अधिकारियों को अलग-अलग ज्ञापन देकर छात्राओं को नि:शुल्क बस पास तुरन्त उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिनिधिमण्डल में छात्र नेता उमेश कुमार, कविता, प्रतिभा, स्फूर्ति, मनीषा व अनिल कुमार शामिल थे।

छात्र प्रतिनिधिमण्डल ने अधिकारियों को बताया कि अभी भी बहुत सी छात्राओं को बस पास नहीं मिले हैं। पहचान पत्र दिखाने के बावजूद उनसे किराया मांगा जाता है। इसलिए सरकार के घोषणा अनुसार तुरन्त प्रभाव से छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क बस पास जारी करने व तब तक बस कण्डक्टरों व निरीक्षकों को कॉलेज पहचान पत्र पर नि:शुल्क यात्रा करने की हिदायतें जारी करने और इसकी एक प्रति सभी शिक्षण संस्थानों के मुखियाओं को भेजी जाने की छात्र संगठन ने मांग की। छात्र संगठन ने यह भी मांग की है कि निजी संस्थानों की छात्राओं को भी यह लाभ दिया जाए। जिन छात्र-छात्राओं ने पहले ही पैसे देकर बस पास बनवा लिया है उन्हें 1 जनवरी 2014 के बाद का पैसा वापस लौटाया जाए। संगठन ने उपायुक्त से यह भी मांग की है कि दाखिलों व रोजगार के लिए आवेदन शुल्क भी आधा करने का आदेश लागू किया जाए।

शहीद रामप्रसाद बिस्मिल-अश्फाक उल्ला को याद किया

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड राजेन्द्र सिंह

ताउडू (हरियाणा): 19 दिसम्बर को स्थानीय पचगांव चौक, नूंह रोड़, तावडू में आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी योद्धा अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व अश्फाकउल्ला खां का शहादत दिवस सम्मानपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर ऑल इण्डिया डीएसओ व ऑल इण्डिया डीवाईओ की ओर से संयुक्त रूप से उनकी स्मृति सभा की गयी जिसकी अध्यक्षता शाहिद मास्टर चीला ने की। सभा में मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने इन महान शहीदों के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डालते हुऐ कहा कि इन शहीदों की कुर्बानी और आजादी आन्दोलन का सारा फल देश के पूंजीपतियों ने हड़प लिया और मेहनतकश जनता ठगी गई। आजादी के 66 साल बाद भी जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और शोषण-जुल्म से त्रस्त है। हर तरह के शोषण से मुक्ति का उन शहीदों का सपना अभी भी अधूरा है। उनसे सीख लें और वर्तमान में अपना फर्ज निभायें।

एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव कॉ. हरीश, डीवाईओ के स्थानीय युनिट इंचार्ज कॉ. महेश, डीवाईओ के सदस्य चमन, बसंत लाल, चीला गांव के सरपंच सद्दीक, देवेन्द्र, सोनू आदि ने भी अपनी बात रखी। सभा की शुरूआत क्रान्तिकारी गीतों से हुई।

मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन

सरायकेला खरसवां : गत दिनों छात्रों ने अपनी ज्वलंत मांगों को लेकर ऑल इण्डिया डीएसओ के बैनर तले सिंहभूम कॉलेज चाण्डिल में जुलूस-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इण्डिया डीएसओ के जिला सचिव अनंत महतो ने किया। प्रदर्शन में काफी छात्र शामिल हुए और नारे लगाये।

पीतल मजदूरों ने किया संघर्ष का ऐलान

मुरादाबाद (उ.प्र.): 11 जनवरी को एआईयूटीयूसी सम्बद्ध पीतल मजदूर यूनियन मुरादाबाद की आम सभा में शासन-प्रशासन द्वारा किए जा रहे पीतल दस्तकारों/मजदूरों के शोषण-उत्पीड़न पर गहन चर्चा की गई और इस पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड इस्लाम अली ने की और संचालन कॉमरेड सुरेशपाल सिंह द्वारा किया गया।

सभा में बोलते हुए ऑल इण्डिया यूटीयूसी के प्रदेश सचिव कॉमरेड विजयपाल सिंह ने कहा कि एक ओर सरकार उद्योगपतियों को हजारों-करोड़ की रियायतें दे रही है, उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं, दूसरी ओर गरीब दस्तकारों का कर्ज वसूली के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। यह हरगिज नहीं चलेगा। इसके लिए पीतल दस्तकारों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।

सभा में सर्वसम्मति से क्रमवार आन्दोलन चलाने, आगामी 27 जनवरी को जिला मुख्यालय पर विशाल रैली आयोजित करने का फैसला किया गया। सभा में मो. हारून, मौलाना सुहैल, मौ. इरशाद, सुनील दूबे, रामरतन सैनी, अफसर अली, छोटे भाई, तसलीम अहमद, इस्लाम अली, मौ. नासिर, मौ. दाऊद, मौ. दिलशाद, रईस अहमद आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

यौन अपराध, अश्लीलता व नशाखोरी के विरोध में धरना

मुजफ्फरपुर (बिहार) : मड़वन प्रखंड के महमदपुर सूबे गांव की एक किशोरी के साथ हुए बलात्कार के विरोध में 10 जनवरी को गांव की आधा दर्जन महिलाएं समहरणालय पहुंची थीं। यह बात गांव के मुखिया के पुत्रों को रास नहीं आयी। मुखिया के पुत्रों ने यौन अपराध के खिलाफ धरना दे रही महिलाओं के परिजनों की जमकर पिटाई की। उन्होंने समाहरणालय आयीं सकीला खातून व नुसरत की मां फातिमा खातून को पीटकर जख्मी कर दिया। किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में फातमा खातून गवाह बनी थी। मुखिया के पुत्रों पर आरोप है कि वे केस खत्म कर यौन उत्पीड़न के आरोपी इश्तेयाक को बचाना चाहते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपी इश्तेयाक तथा उसे बचाने वाले व महिलाओं की पिटाई करने वाले मुखिया पुत्रों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, अश्लीलता व नशाखोरी के विरोध में एआईएमएसएस ने समाहरणालय में धरना दिया।

धरना को संबोधित करते हुए एआईएमएसएस राज्य कमिटी सदस्या कॉ. अनामिका ने कहा कि देश में बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दुधमुंही बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ भी ऐसी पाशविक घटनाएं घट रही हैं। आज देश में हर 54 मिनट में एक बलात्कार, 51 मिनट में एक यौन उत्पीड़न, 26 मिनट में एक छेड़छेड़ की घटना तथा 102 मिनट में एक दहेज हत्या की घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने कहा कि आज धड़ल्ले से शराब के ठेकों के लाइसेंस दिये जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों-अपराधों के खिलाफ ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की जरूरत पर बल दिया। इस मौके पर ऑल इंडिया डीएसओ के जिला सचिव लालबाबू राय, इबरान खातून, समीदा खातून, सुनीता देवी, शोभा देवी, आसमा खातून और निर्मला ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने बलात्कार के आरोपी इश्तेयाक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उसे कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही बलात्कार के आरोपी को बचाने की कोशिश करने वाले तथा प्रतिवादी महिलाओं की पिटाई करने वाले मुखिया पुत्रों की भी गिरफ्तारी तथा सजा दिलाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमा देवी ने की और संचालन एआईएमएसएस की जिला संयोजिका कंचन कुमारी ने किया।

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन तेज करो

एआईएमएसएस, एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ द्वारा 30 दिसम्बर 2013 को जन्तर-मन्तर पर आयोजित प्रतिवाद सभा में कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण

अध्यक्ष जी,

जस्टिस सुरेश हॉस्बेट जी, एमएसएस, डीवाईओ, डीएसओ के नेतागण कॉमरेडों और दोस्तो,

यह कहने की जरूरत नहीं है कि जो आन्दोलन आपने एक साल पहले शुरू किया था और आज देश भर में आपने इसे प्रसारित कर दिया, एवं और भी उन्नत रूप से ले जा रहे हो यह एक ऐतिहासिक घटना है। लेकिन आपको समझना होगा कि कोई भी आन्दोलन यदि समस्या का कारण न ढूँढ़ सके तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ इससे ही नहीं होता है कारण को जानते हुए भी यदि आन्दोलन के सामने एक महान आदर्श न हो, यदि आन्दोलन के नेता कार्यकर्त्ता एक उन्नत रूचि-संस्कृति व नीति-नैतिकता के आधार पर आन्दोलन को आगे न ले जाएं तो भी आन्दोलन सफल नहीं होता है। यूरोप में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ, ग्रीक से लेकर स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल तक यूरोप के सारे देशों में, मिडल ईस्ट में आखिरकार अमेरिका में भी जो विशाल आन्दोलन आपने देखा वह बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद जिस लक्ष्य की ओर इसे जाना चाहिए था, समाज में जो एक आमूल-चूल परिवर्तन आना संभव था वह हो नहीं पाया। कारण क्या है? लेनिन जिन्होंने प्रथम सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति करके दिखा दिया था कि मजदूर ही दुनिया को बदलेंगे साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांति नहीं होगी इसी तरह एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना भी क्रांति नहीं होगी। लाखों-करोडों लोगों का इतना बड़ा आन्दोलन मिस्र में आपने देखा जो आज भी चल रहा है, वह समाज में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं ला सका। इसलिए हमें इन सब आन्दोलनों से सबक लेना है। चाहे आन्दोलन कितना ही बड़ा हो, विशाल हो, कितना ही ताकतवर हो, मगर एक महान उद्देश्य बिना, एक महान आदर्श के बिना सफल नहीं हो सकता है। आपके आन्दोलन के समाने आदर्श भी है, आपने कारण भी समझ लिया, इसलिए भरोसा है कि सफल होगा ही। सबसे बड़ा सवाल जो लोग आन्दोलन कर रहे हैं उनके सामने तो एक सवाल है ही, आम जनता में भी है कि यह जो एक महिला पर हमला हुआ, केवल यही तो समस्या नहीं है, बच्चों पर हमला हो रहा है। इस दिल्ली शहर में हर रोज 17-18 बच्चे गायब हो जा रहे हैं। देश भर में कितनी महिलाओं को गुण्डे जबरन उठा कर ले जा रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं। ऐसी कितनी घटनाओं की खबर सामने आती है? भ्रष्टाचार में तमाम समाज डूब गया है। लोग परेशान हैं। आर्थिक राजनैतिक शैक्षणिक हर क्षेत्र में समस्या, दिन प्रतिदिन ये समस्याएं संकट में तब्दील हो रही हैं। ये हल होना तो दूर की बात रही, बढ़ती ही जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं। कारण क्या है? आप जानते हैं कि यह जो नशाखोरी बढ़ रही है यह एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो अश्लील विज्ञापन, सिर्फ दिल्ली शहर में ही नहीं, प्रिण्ट मीडिया में, अखबारों में हर रोज छप रहे हैं, सिनेमा ज्यादा से ज्यादा सैक्स और हिंसा परोस रहा है। ये सभी कारण हैं। इससे भी बड़ा कारण है कि अपराधियों को पकड़ना उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करना तो दूर की बात बल्कि ज्यादा से ज्यादा मामलों में पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। सर्वोपरि, जहां आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और मर्यादा की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, देश में केन्द्र हो या राज्य सरकारें कोई भी इस जिम्मेदारी को निभा नहीं रही है बल्कि सरकारों के जनविरोधी रवैये और देश की न्याय प्रणाली के ढीलेपन से अपराधी आश्वस्त हैं कि या तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और यदि होगी भी तो बच निकलने के रास्ते खुले रहेंगे। एक भी सरकार आप बता नहीं सकते हैं जो इसके खिलाफ लड़ती हो, एक जनमुखी नीति लेकर चल रही हो बल्कि ये दिखाना संभव है और वास्तविक है कि तमाम सरकारों ने जनविरोधी नीतियां लागू करके स्थिति को इतना गम्भीर बना दिया है।

इस दिल्ली में 1984 में सिख-विरोधी दंगे कांग्रेस ने करवाए थे। कितनी सारी महिलाओं, बुजुर्गों, मासूम बच्चों का कत्लेआम किया। यहां तक कि जला कर मार दिया। कितना बड़ा अपराध किया, फिर भी क्या इन अपराधियों को उचित सजा मिली? नहीं मिली। बीजेपी जिस नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रही है उस नरेन्द्र मोदी की सरकार ने गुजरात में क्या किया आप जानते हो। वे बड़े आश्वस्त हुए कि कानूनी तौर पर उनको राहत मिली है। हाँ बुर्जुआ कोर्ट में उनको राहत मिली, लेकिन जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि वहां क्या हुआ था! हजारों-हजार मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। गर्भवती महिला का पेट चीर कर बच्चा निकाल कर मशाल पर जलाया गया। उन्होंने नहीं किया! ये क्या बात हुई? वे तो मुख्यमंत्री थे। उनकी आंखों के सामने ये जो भयंकर अत्याचार बुजुर्गों से लेकर महिलाओं पर बच्चों पर जो हमला हुआ, आप एक को भी बचा नहीं सके। इससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? नागरिकों की सुरक्षा करना आपका काम था। क्या आप कर सके? एक को भी क्या आप बचा सके? यदि नहीं बचा सके तो आप कितने बड़े प्रशासक हैं–क्या इसका जवाब आप दोगे? कानूनी तौर पर आपकी मुक्ति हुई, यह ठीक है लेकिन इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री बन कर आप सुशासन दोगे, कैसे दोगे? एक व्यक्ति पर भी यदि हमला होता है तो सरकार का फर्ज बनता है उसको बचाना। क्या आपने बचाया? आपके शासन में हजारों लोग खुल्लमखुल्ला खून करने लगे, आप आंख बन्द कर बैठे रहे। समाज जाएगा कहाँ? ये समझना चाहिए। इसलिए जनता के सामने एक बड़ा सवाल है कि ये क्यों हो रहा है? कारण हम बता सकते हैं, हाँ, यह बात ठीक है कि शराब, नशाखोरी की वजह से ऐसा भयंकर एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बड़े होते हुए सैक्स और हिंसा देख रहे हैं। इस माहौल में ही बड़े हो रहे हैं। इसे हासिल कर रहे हैं। आचरण में भी आ रहा है, हाँ ये भी कारण है लेकिन सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही है, इसका मुकाबला नहीं कर रही है, इसे बैन नहीं कर रही है, बल्कि प्रोत्साहित कर रही है। जैसे दामिनी पर हमला होने के बाद इण्डिया गेट और विजय चौक पर जो विशाल विक्षोभ प्रदर्शन हुआ उस पर सरकार ने वाटर केनन छोड़कर ठण्ड के दिनों में 18-19 दिसम्बर को टीयर गैस, लाठी, सब चलाई। इससे क्या संदेश गया? यह अपराधियों को प्रोत्साहित करने के सिवाय और क्या था कि आप कुछ भी करो, यदि उसके विरोध में प्रतिवाद होगा तो हम पीटेंगे। यही तो संदेश गया। तो सरकार क्या कर रही है? यदि हम कहें कि यह नशाखोरी के कारण हो रहा है तो यह नशाखोरी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सरकारें प्रोत्साहन दे रही हैं। विज्ञापन अश्लील रूप क्यों ले रहा है? क्योंकि सरकारें इजाजत दे रही हैं। अन्ततः यह सब रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम एक बात में कह सकते हैं कि ये पूँजीवादी देश है और शोषणमूलक समाज है तो सरकार पूँजीपतियों की स्वार्थ रक्षा कर रही है। सही है, यह बात तो सच है। आज पूँजीपति वर्ग सर्वहारा क्रान्ति के डर से जनता में सांस्कृतिक पतन के लिए जो कुछ करना है वह सभी कुछ कर रहा है ताकि जनता अन्याय अत्याचार के खिलाफ हिम्मत से खड़ी ना हो सके। सरकार यह कर रही है लेकिन फिर भी सवाल उठता है, उठना भी चाहिए कि शुरूआती दिनों में तो बुर्जुआ सरकार जब पहले पहल यूरोप में आई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन, इण्डस्ट्रीयल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैण्ड, अमेरिकन वार आफ इण्डिपेण्डेंस ये सब जिसे हम बुर्जुआ क्रान्ति कहते हैं उस जमाने में तो ऐसा नहीं था। बुर्जुआ सरकार होते हुए भी इस तरह का आचरण नहीं होता था। बुर्जुआ नेताओं का स्तर भी आज जैसा गिरा हुआ नहीं था बल्कि उस जमाने में रूसो, वाल्टेयर जैसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था। कॉपरनिक्स, गैलीलियों, न्यूटन जैसे

महान वैज्ञानिकों का जन्म हुआ था ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ था। साहित्य, शिल्पकला हर क्षेत्र में विकास हुआ था। चार्ल्स डिकन्स, विक्टर ह्युगो, मिल्टन, टेनिसन जैसे साहित्यकारों, माइकल एंजलों, रैफल, रौदां जैसे महान मूर्तिकारों और ऐसी कितनी ही महान विभूतियों का जन्म हुआ था। जीवन के हर क्षेत्र में विकास हुआ था। आज किसी भी पूंजीवादी देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज सभी पूंजीवादी देशों में जीवन के हर क्षेत्र में जो पतन हो रहा है इसका क्या कारण है? इसे हमें ढूंढ़ना चाहिए। बल्कि यह बुर्जुआ वर्ग ही आज इस सारी अश्लील अपसंस्कृति को प्रोत्साहन दे रहा है। जनता, खासकर छात्रों-नौजवानों की नैतिक रीढ़ को तोड़ डालने का प्रयास क्यों कर रहा है –यह हमें गहराई से समझना चाहिए। इसका कारण जो महान मार्क्स ने दिखाया था उसे आपको जो आन्दोलन को नेतृत्व देगे, गहराई से समझना पड़ेगा। उन्होंने दिखाया था कि इतिहास में कोई भी चीज वस्तुजगत में हो, प्रकृति में हो, समाज में हो, जीवन में हो, जो चीज आती है वह शुरूआती काल में प्रगतिशील रहती है, यहाँ तक कि क्रान्तिकारी चरित्र लेकर ही आती है। पुराने समाज को तोड़कर जब एक नई सभ्यता का जन्म होता है, जैसे बुर्जुआ पूँजीवादी सभ्यता की सृष्टि हुई थी, उस जमाने में इसका चरित्र क्रान्तिकारी था, प्रगतिशील था, लेकिन मार्क्स ने दिखाया था कि जो कुछ आता है उसकी वृद्धि होती है, विकास होता है, विकास होते-होते वह निःशेषित हो जाता है। इसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है। उसको चले जाना चाहिए। यह हर क्षेत्र में होता है। जिन्दगी में होता है। जब जन्म हुआ, तो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन मरना भी है। यह स्वाभाविक है। समाज व्यवस्था में भी ऐसा ही होता है। एक समाज व्यवस्था भी जब अस्तित्व में आती है, तब प्रगतिशील रहती है, बहुत दिनों तक उसका विकास होता है, वृद्धि होती है, होते-होते जब विकास के चरम स्तर पर पहुँच जाती है उसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने और एक चीज दिखाई थी। उसे हमें गहराई से समझना चाहिए। वह है प्रकृति जगत में जैसे किसी वस्तु में अपने आप परिमाणगत परिवर्तन होते-होते गुणगत परिवर्तन हो कर आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है अर्थात् उसमें क्रान्ति हो जाती है। समाज में ऐसा नहीं होता है। नियम एक ही है लेकिन और एक विशेष कारक उसमें काम करता है वह है सामाजिक परिवर्तन में चेतना की, इंसान की चेतना की एक भूमिका होती है। यदि इंसान की सचेत भूमिका न हो तो मूलभूत परिर्वतन अपने आप नहीं होता है। पूँजीवाद आया कई सौ साल पहले। मार्क्सवाद को विकसित करते हुए लेनिन ने 1902-3-4 में उस समय दिखाया था कि पूँजीवाद अपने विकास के चरम स्तर, साम्राज्यवादी स्तर पर पहुँच गया है। इस साम्राज्यवादी स्तर में पहुँच कर पूँजीवाद मरणासन्न हो चुका है। जब लेनिन कहते हैं कि पूंजीवाद की चरम अवस्था है साम्राज्यवाद (हाईयेस्ट स्टेज ऑफ डेवेलप्मेण्ट ऑफ कैपिटलिज़्म इज इम्पीरियलिज़्म) तो इसका मतलब ही है कि इसके विकास की और तनिक भी गुंजाइश नहीं है। यहीं से उसका पतन शुरू होता है और हुआ भी। जो

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण

(पृष्ठ 3 का शेष)

समाज व्यवस्था पुरानी नहीं हुई है, मरणासन्न नहीं हुई है उस समाज व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते हो चाहे कितनी भी लड़ाई करो, जान दे दो, कुर्बानी करो, खून बहाओ। चूँकि पूँजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाशील बन चुका था तभी लेनिन ने 1917 में रूस में क्रान्ति करके सर्वहारा क्रान्तिकारी एक नई सभ्यता को जन्म देते हुए दिखा दिया था कि वास्तव में ही पूँजीवाद प्रतिक्रियाशील बन चुका है। कब? 100 से भी अधिक वर्ष पहले पूँजीवाद प्रतिक्रियाशील बन चुका। इसके विकास की और संभावना कुछ भी नहीं है। यदि समाजवादी क्रान्ति करके नई सभ्यता की सृष्टि हम नहीं कर सके तो यह पूँजीवादी व्यवस्था दिन पर दिन पतित होती रहेगी। जनता को भी साथ-साथ पतित करती जाएगी। इससे मुक्ति नहीं। यह जो पूँजवादी सरकार आज कर रही उस युग में नहीं किया था बल्कि उस युग में सामाजिक प्रगति का रास्ता खोल दिया था। शिल्प-उद्योग का रास्ता, जिसे हम औद्योगिक क्रान्ति कहते हैं, उसका रास्ता खोल दिया था। इसके लिए ज्ञान-विज्ञान का रास्ता खोल दिया था। एक नई सभ्यता के लिए एक नई नीति-नैतिकता, एक नई संस्कृति, एक नये जीवनबोध के आधार की सृष्टि की थी। साम्राज्यवादी स्तर पर आने के बाद उसका पतन शुरू हो गया। पहले की उसकी नीति-नैतिकता भी ध्वस्त हो गई। वह अब और काम नहीं कर सकती है। उन दिनों की नीति-नैतिकता लेकर आज समाज की प्रगति नहीं हो सकती है। आज यहाँ कांग्रेस के कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिनका नारा या आदर्श कहिए है भारत माता की जय, वन्दे मातरम। जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी आप याद कीजिए उन दिनों जो संघर्ष में आते थे, वे वन्देमातरम कहते थे, उनको लाठी गोली का मुकाबला करना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था, इससे चरित्र का निर्माण होता था। जो आदर्श त्याग सिखाता है, बलिदान सिखाता है, जान न्योछावर करने की तमन्ना पैदा करता है वह एक नई संस्कृति को जन्म दे सकता है। आज जब आजादी के बाद पूँजीपति वर्ग सत्ता में आ चुका है तब और कोई खुदीराम पैदा नहीं हो रहा है। वह आदर्श लेकर और कोई खुदीराम नहीं बनेगा, वह आदर्श लेकर चन्द्रशेखर आजाद और नहीं बन सकते, उसी आदर्श को लेकर नेताजी नहीं बन सकते और भगतसिंह भी नहीं बन सकते। आज वह आदर्श लेकर चला नहीं जा सकता। इसी पूँजीवादी आदर्श, बुर्जुआ आदर्श को ले कर ये कांग्रेसी नेता आज घोटालों में इतना फंस गए। भ्रष्टाचार में डूब गए। ऐसा हो सकता है और होगा। बीजेपी भी उसमें डूबी है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी बना कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बातें कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन क्या कर पाएंगे? उनका आदर्श भी इस बुर्जुआ आदर्श के सिवाय और कुछ नहीं है। व्यक्तिवादी चिन्तन को आधार करके ही उनका आदर्श है। ईमानदार हो सकते हैं लेकिन सिर्फ ईमानदारी से ही इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा? अन्याय-अपराध क्यों हो रहा है? सिर्फ कुछ भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करने से ही क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार फाइट करने से जाएगा? यह जो महिलाओं पर इतना बड़ा अत्याचार चल रहा है, बच्चे-बच्चियों पर जो हमला हो रहा है, उसका क्या करोगे? क्या रोक पाओगे? क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था मरणासन्न हो गई है इसलिए इसकी नीति-नैतिकता भी मर रही है। इस पूँजीवाद की जो भी सेवा करेंगे वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पायेंगे। एक-दो व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है लेकिन हजारों लोग इसका शिकार बन रहे हैं। एक रेलवे टिकट चैकर भी भ्रष्टाचार का शिकार है। आपको रेलवे टिकट आरक्षण नहीं मिला, आपकी माता जी मृत्यु शैया पर हैं, आपको जाना है। आपकी इस कमजोरी को जानते हुए टिकट चैकर आपसे पैसा लेते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैल गया है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेण्ट है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। कैसे दूर करोगे? दो चार आदमियों को, एक ए. राजा को जेल भेज देने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? इतना आसान नहीं है और जब तक यह स्थिति बरकरार है यदुरप्पाओं और ए. राजाओं का भी जन्म होता रहेगा। भ्रष्टाचार हो, महिलाओं पर हमला या अत्याचार हो, अपराध हो, ये समाज में यह लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि पूँजीवाद आज मरणासन्न हो चुका है, प्रतिक्रियाशील हो चुका है। यह पूंजीवादी सभ्यता एक मरणासन्न सभ्यता (डाइंग सिविलाइजेशन) है। इसमें जो कुछ महान है, जो कुछ सुन्दर है वह सभी कुछ मर रहा है। मानवीय मूल्यबोध मर रहे हैं। इसी कारण इतनी भयंकर स्थिति पैदा हुई है। एक नई सभ्यता की सृष्टि करने का आदर्श यानी समाजवादी आदर्श को लेकर जो उच्च नीति-नैतिकता के आधार पर इस पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे वे ही इस भ्रष्टाचार का मुकाबला कर पायेंगे। हमारे कॉमरेडों को देख कर लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में, यहां तक कि डीएसओ, डीवाईओ, एमएसएस जैसे संगठनों में भी जो पार्टी नहीं जन-संगठन हैं, इनमें भी जो नीति-नैतिकता, जो आदर्श, जो चरित्र, जो अनुशासन, जो सामाजिक दायित्वबोध हम देखते हैं वह कहाँ से आ रहा है? यह आ रहा है पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के चिन्तन से, एक महान आदर्श से, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिन्तन से। इसमें है नई संस्कृति। यह आपको गहराई से समझना चाहिए। तो लड़ाई आखिरकार पूँजीवाद के खिलाफ है। यह पूँजीवाद-विरोधी आन्दोलन यदि बढ़े, इसके लिए आपको इस राजसत्ता से टक्कर लेनी पड़ेगी, जान भी देनी पड़ेगी, तभी तो आप नई सभ्यता की सृष्टि कर सकते हैं। अन्याय-अत्याचार जहाँ से आ रहा है उसके विरोध में जब आप लड़ाई लड़ोगे तब एक चरित्र निर्मित होगा। त्याग की भावना आएगी। जान देने की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना तभी आएगी। आप लोग वही लेकर लड़ रहे हो। इसीलिए आप देखोगे कि यह दामिनी हत्याकाण्ड, यह जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हजारों, लाखों-लाख लोगों ने विरोध किया। आज वे सब कहाँ हैं? इसमें कोई शक नहीं कि उनके उस विरोध ने एक महान इतिहास रचा। लेकिन आज वे कहां गए? एक दिन मना सकते हैं 16 दिसम्बर जिस दिन उन पर हमला हुआ था या 29 दिसम्बर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी—ये दिन आप मना सकते हो। लेकिन आन्दोलन तो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास वह विचार नहीं है। इस विचार को आपको ले जाना पड़ेगा। आप जो आन्दोलन कर रहे हो, आपको भी गहराई से समझना चाहिए, यह सिर्फ सरकार पर कुछ दबाव बनाने के लिए एक राजनीतिक आन्दोलन नहीं है। हां, वह भी है। यह जो कानून-व्यवस्था है इसमें जो नाबालिग व्यक्ति जिसने महिला पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया, वह बालिग होने में सिर्फ तीन महीने कम था। इसलिए उसे तीन साल की ही सजा मिली। क्योंकि कानून में इतना ही है। इस कानून को बदलने के लिए आप लड़ रहे हो, ताकि ऐसे व्यक्ति को भी उचित सजा मिले। यह एक लीगल मूवमेण्ट भी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि यह एक सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन है। समाज की चिन्तन की यह धारा, बुर्जुआ वर्ग का चिन्तन, बुर्जुआ व्यक्तिवादी चिन्तन जो आज सिर्फ व्यक्तिवाद ही नहीं, बल्कि व्यक्तिकेन्द्रित चिन्तन, अत्यन्त नीच चिन्तन (पोल्यूटेट इण्डिविजुलिज्म), घोर व्यक्तिगत स्वार्थ, खुदगर्जी जिसे हम स्वार्थपरता कहते हैं वह पैदा हो गया है जिससे इतना सब हो रहा है। स्वार्थपरता एक घृणित चीज होती है लेकिन उससे भी भयंकर व्यक्तिवाद ही नहीं बल्कि आत्मकेन्द्रित चिन्तन यह है कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छी चीज बन रही है, बस मेरे लिए बन रही है, मेरे सुख के लिए, मेरे भोग के लिए है। यह जो चिन्तन इतना गिरा हुआ चिन्तन है समाज को ध्वस्त कर देता है।

समाज में इतना जो कुछ देखते हो अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवादी चिन्तन और पूँजीवाद ने एक भयंकर संकट को पैदा किया है। हर क्षेत्र में भविष्य अनिश्चित हो गया है। इस अनिश्चित भविष्य में कल क्या होगा? यह चिंता सता रही है कि हमारे लड़के को नौकरी मिलेगी या नहीं, उसको सम्पत्ति मिलेगी कि नहीं। इसीलिए जब सत्ता में है, जब पावर में है, नीति नैतिकता की कोई परवाह नहीं तो भ्रष्ट हो जाता है। हो रहा है। व्यक्तिवादी चिंतन जो आज पोल्यूटिड अर्थात दूषित हो चुका है वह आज इंसानों को समाज से विमुख बना रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई करते हुए सामाजिक चिंतन लाकर ही मौजूदा सांस्कृतिक पतन को रोका जा सकता है। यह चिंतन केवल मार्क्सवाद ही दे सकता है। जिसे हमारे देश में कॉमरेड शिवदास घोष ने ठोस रूप से लागू किया। आप इसको ही ले कर लड़ रहे हैं। अत: यह एक बहुत ही महान आन्दोलन है। यह पुराने चिन्तन, पुरानी भावना-धारणा, पुरानी नीति-नैतिकता की सोच इस सब कुछ का मुकाबला करते हुए एक नई सभ्यता की सृष्टि, नई नीति-नैतिकता, नई संस्कृति की सृष्टि के लिए लड़ाई है। नए जीवनबोध के लिए लड़ाई है। सामाजिक जीवन, समाजवादी चिन्तन को लाने के लिए आप लड़ रहे हो। ये मूल आन्दोलन है। साथ ही साथ इस नशाखोरी को बन्द करने के लिए, अश्लील विज्ञापन को बन्द कराने के लिए, सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है। शिक्षा में अश्लीलता को लाया जा रहा है। कक्षा छ: से सैक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन आखिरी लड़ाई सामाजिक चिन्तन को बदल देने की है। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि हमारे देश का आजादी आन्दोलन ही था बुर्जुआ जनवादी क्रांति का संघर्ष। चूँकि हमारे देश का आजादी आन्दोलन साम्राज्यवादी युग में अर्थात पूँजीवाद के संकट के युग में, साम्राज्यवादी युग में अर्थात जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजीवाद प्रतिक्रियाशील बन चुका था तब हुआ इसलिए यह सामंती चिन्तन के खिलाफ, सामंती संस्कृति के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष नहीं कर पाया बल्कि इसके साथ समझौता किया। फलस्वरूप सामंती चिन्तन रहने के कारण इस पुरुषप्रधान समाज में महिला के प्रति जो दृष्टिकोण, जो नजरिया है वह मुख्यत: सामंती है। महिला के भोग-विलास की वस्तु के रूप में देखते हैं। उसके साथ दूषित बुर्जुआ व्यक्तिवादी संस्कृति मिल गई है। इन दोनों के मिश्रण से समाज में एक खिचड़ी संस्कृति पैदा हुई है। इसके खिलाफ आपकी लड़ाई है। कठिन लड़ाई है लेकिन महान लड़ाई है। यह आपके दिल में रहना चाहिए कि आप समाज का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए लड़ रहे हो। नई सभ्यता की सृष्टि आप करोगे। ये विश्वास लेकर आपको लड़ना है और यह यदि आप कर सकोगे तभी समाज में नये चिन्तन, नई सभ्यता की सृष्टि होगी। खास करके छात्रों-नौजवानों में एक नई संस्कृति का जन्म होगा। आज सबसे बड़ा काम आप कर रहे हो। कॉमरेड, मैं इतना ही कहूँगा कि जीवन के सभी पहलुओं को समेटे हुए यह एक सर्वसमावेशी आंदोलन है। इसे दूसरा और कोई नहीं कर सकता है क्योंकि आपके पास ही जीवन के हर पहलु को समेटे हुए एक सामग्रिक दृष्टिकोण है। दूसरे इस आंदोलन में जरूर कुछ योगदान कर सकते हैं। इसलिए सभी को जुटाने का प्रयास करिए लेकिन आंदोलन को नेतृत्व आपको ही देना है। साथ ही यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यह एक कठिन संघर्ष है।

देखिए कल मावलंकर हाल में आपका अखिल भारतीय सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। सिर्फ संख्या के हिसाब से ही नहीं, संख्या के हिसाब से भी अभूतपूर्व था। जस्टिस राजेन्द सच्चर जो एक जाने-माने व्यक्ति हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, जो आज भी जनता के लिए लड़ रहे हैं कल सम्मेलन में उन्होंने बताया कि गद्दर आन्दोलन की 100वीं वर्षगांठ पर मैंने देखा कि इस मावलंकर हाल में भीड़ समा नहीं रही थी और आज उसी तरह का समावेश देख रहा हूँ। सम्मेलन का उद्घाटन किया था जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण ने जो न केवल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बल्कि बीजेपी शिवसेना ने मिलकर जो बम्बई दंगे कराए थे, उनकी जांच करने के लिए जो 'श्रीकृष्ण कमीशन' बना था, उन पर उन्होंने अति वास्तविक रिपोर्ट दी थी, जिसकी वजह से उनका नाम ने जनवादी चिन्तन रखने वाले लोगों में एक विशेष स्थान ले लिया था। इसके अलावा बाम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुरेश हास्बेट को अभी आपने सुना। ये लोग जिनके विचार इतना महत्व रखते हैं लेकिन प्रमुख अखबारों ने अनदेखा किया। यहाँ-वहाँ कल जो छोटे-छोटे प्रोग्राम हुए उनका फोटो भी छपा है, खबर भी छपी है, सब कुछ छपा है। इससे क्या साबित होता है? क्या इनकी जानकारी में नहीं था? आपके कार्यकर्ताओं ने कई दिनों से इन प्रेस के दफ्तरों में जा-जाकर आमन्त्रित किया, प्रेस कांफ्रेंस की। उन्हें मालूम है लेकिन दो एक

(शेष पृष्ठ 7 पर)

आसाम बंध ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जगह देने के लिए इस्तेमाल किया गया। हालाँकि जनदबाव के चलते ऐसे नितांत प्रभावहीन और फिजूल के अधिकतर उपरि सदनों को भंग कर दिया गया था। 28 प्रदेशों में से केवल 6 में ही अब इस विधान परिषद को अपने तुच्छ स्वार्थ में उन राज्यों की शासक पार्टियों द्वारा कायम रखा गया है। अब इस विधान परिषद रूट के जरिये अनुचित सुविधाएं और लाभ हासिल करने के प्रयास नये सिरे से हो रहे हैं। यह भी स्मरण रहे कि पश्चिम बंगाल की तृण मूल कांग्रेस सरकार द्वारा भी सत्ता में आने के तुरन्त बाद ऐसा ही कदम उठाने का प्रयास किया गया था और हमारी पार्टी के एक-दो सदस्यों को जगह देने का प्रलोभन भी दिया गया था। लेकिन हमारी पार्टी के जबरदस्त विरोध के चलते वह इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा पायी थी।

आसाम में शासक कांग्रेस द्वारा पार्टी के अन्दर बढ़ते गुटबाजी के टकरावों और अन्दरूनी झगड़ों से पार पाने के लिए इस प्रस्ताव को पेश किया गया है ताकि झगड़ रहे नेताओं को उपरि सदन में सीट देकर संतुष्ट किया जा सके और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये घृणित अन्दरूनी झगड़े-फसाद उसकी चुनावी सम्भावनाओं को खतरा न पहुँचा पायें। यह उन नेताओं को भी जगह देने का नुस्खा है जो लोगों द्वारा नकार दिये गये हैं। इस विधान परिषद की रचना अनुसार 6 नेताओं को मंत्रिमण्डल में शामिल किया जा सकता है। विधान परिषद के 42 सदस्य भारी वेतन, आवास, ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाओं और भत्तों सहित तमाम राजकीय विशेषाधिकारों के पात्र होगें जो विधान सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। यह प्रस्ताव पेश करने के पहले दिन से ही स्पष्ट संकेत थे कि इसके तमाम सदस्य मुख्यत: और अधिकतर शासक पार्टी से ही मनोनीत किये जायेंगे। कांग्रेस अपने अन्दरूनी झगड़ों को इन प्रलोभनों और रिश्वतों से शांत करना चाहती है। आसाम में विधान परिषद कायम करने के पीछे यही घिनौना मकसद था।

राज्य की मेहनतकश जनता ने इस बंध को सफल बनाने के लिए व्यापक समर्थन दिया, एक सच्चाई जिसे मीडिया को भी स्वीकार करना ही पड़ा। इस बंध की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आसू(एएएसयू) के संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी आन्दोलन के दिनों से ही आसाम के लोग बार-बार इस या उस बहाने होने वाले बंधों से रूबरू होते आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बंध जनहित से सरोकार रखने वाले किसी मुद्दे को लेकर नहीं होते थे। इसका फायदा उठा कर मीडिया की मदद से शासक बुर्जुआ वर्ग ने अपने निहित स्वार्थ में सभी हड़तालों और बंधों के खिलाफ बदनाम करने का अभियान छेड़ दिया था। इसके फलस्वरूप फिलहाल लोगों में एक हड़ताल-विरोधी मानसिकता पनप गई थी। इसे भांप कर सरकार ने पहले ही बंध-विरोधी कानून का मसौदा तैयार कर रखा है। इस संदर्भ में ही एसयूसीआई(सी) के आह्वान पर 3 जनवरी के बंध को स्वत:स्फूर्त मिले व्यापक समर्थन ने खास अहमियत अख्तियार कर ली है जो एक नये परिदृश्य के खुलने की ओर इशारा है। गाँव-कस्बों से लेकर स्कूल-कॉलेजों, दफ्तरों-कचहरियों तक, यातायात-परिवहन से लेकर व्यापार-वाणिज्य तक जनजीवन की तमाम गतिविधियाँ इस दिन ठप पड़ गई थी। गुवाहाटी महानगर के पान बाजार, फेंसी मार्केट, लखरा-आईएसबीटी रोड़, जी एस रोड़, पलटन बाजार जैसे भीड़भाड़ भरे व्यस्त स्थलों सहित कई क्षेत्रों में बच्चे और किशोर क्रिकेट खेलते देखे गये। गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित प्रमुख शिक्षण संस्थान बंद थे, बैंकों सहित व्यापार-वाणिज्य केन्द्रों के शटर बंद थे। हालाँकि आम दिनों में बहुत ही कम दिखाई देने वाली बसों को इस दिन कुछ ज्यादा ही संख्या में सुनसान सड़कों पर उतारा गया था। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी कुछ को जबरन खोल कर रखा गया था। बंध की ऐसी व्यापक सफलता ने जिलों को भी अपने आगोश में ले लिया था। यहाँ तक कि धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, लक्ष्मीपुर, दरांग, सोनितपुर, नलबाड़ी, नौगाँव, डिबरूगढ़, बरपेटा और अन्य जिलों में भी सब कुछ बंद रहा। पूरे राज्य से पुलिस ने 230 बंध समर्थकों को गिरफ्तार किया। बंध से एक दिन पहले अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं को जिनमें 3 महिला कॉमरेड शामिल थी, पुलिस ने हवालात में डाल दिया था और रात 11 बजे तक बंदी बनाये रखा। लेकिन यह भी निष्फल सिद्ध हुआ। बंध को विफल करने के लिए प्रशासन के ऐसे शर्मनाक प्रयासों के बावजूद इस अनोखे ऐतिहासिक बंध की भारी सफलता ने खुल कर बता दिया कि राज्य के लोग विधान परिषद लागू करने के फैसले को गैर जरूरी और बेकार मानते हुए नकारते हैं। इसने यह भी रेखांकित किया है कि सही नेतृत्व के तहत उठाई मांगों का औचित्य हो तो लोग बेझिझक अपना समर्थन देने के लिए आगे आते हैं।

गौरतलब है कि एक साल पहले तक भी विधान परिषद के खिलाफ जनमत इतना मुखर नहीं था। असल में, इस कदम का जनविरोधी चरित्र जनता के सामने बहुत स्पष्ट नहीं था। इसलिए सरकारी षड्यंत्र सामने आने के तुरंत बाद हमारी पार्टी एसयूसीआई(सी) की आसाम राज्य इकाई ने इस कदम के पीछे छिपे मनहूस मन्सूबे का खुलासा करने के लिए राज्यव्यापी जोरदार संगठित आन्दोलन खड़ा करने की पहलकदमी की थी। बुद्धिजीवियों, प्राध्यापकों को शामिल कराते हुए कई सम्मेलन किये गये, उनके हस्ताक्षरयुक्त वक्तव्य जारी किये गये, जिला और राज्य दोनों स्तरों पर धरने, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित की गई। हमारी पार्टी ने दिखाया कि जब सरकार वित्तीय संकट का बहाना बना कर विकासात्मक प्रोजैक्टों को रोक रही है, कांग्रेसी मुख्यमंत्री बार-बार खजाना खाली होने का रोना रो रहे हैं, वह भी इस हद तक कि सरकारी कर्मचारियों के 33 महीने के बकाया का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है कि कहीं इससे राज्य दिवालिया न हो जाये, तब करोड़ों रुपये खर्च करके इस फिजूल की लेजिस्लेटिव बॉडी को लागू करने का क्या औचित्य बनता है। क्या यह प्रस्ताव लोगों से टैक्स वसूल कर बनाये गये पब्लिक फण्ड को गबन करने के समान नहीं है? तब किसके स्वार्थ में यह विधान परिषद काम करेगी और वह भी आजादी के 66 साल बाद अचानक? पार्टी ने इस साजिश से लोगों को सचेत करने के लिए साल भर से आन्दोलनों का सिलसिला चलाया हुआ था। प्रचार के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने स्वीकारा कि इस प्रस्ताव के पीछे घृणित षड्यंत्र को वे समझ नहीं सके थे। बंध पर पर्चों, पोस्टरों, दीवार लेखन, धरनों सहित गहन प्रचार ने ऐसा एक जबरदस्त प्रभाव छोड़ा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

आसाम बंद के दिन : कुछ झलकियां

मांगों को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा

रोहतक (हरियाणा) : भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन सम्बन्धित ऑल इण्डिया यूटीयूसी ने श्रमिकों की मांगों को लेकर 17 जनवरी को यहां प्रदर्शन किया। यूनियन से जुड़े मजदूर कारीगर पहले मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए और एक जनसभा की जिसे कई श्रमिक नेताओं ने सम्बोधित किया। नारे लगाते हुए श्रमिक लघु सचिवालय पर पहुंचे और निदेशक श्रमिक कल्याण बोर्ड चण्डीगढ़ व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीसी की मार्फत भेजा।

श्रमिकों ने शिकायत की कि पंजीकरण अधिकारी ए डी का रवैया नकारात्मक है। वे इसमें जानबूझ कर बाधा डालते हैं, मजदूरों को धमकाते हैं, कॉपी बनाने में देरी करते हैं, उनमें गलत नम्बर दर्ज करते हैं। इस बर्ताव पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाई जाने, मजदूरों की बेटियों के विवाह की कन्यादान राशि 51 हजार रुपये करने और विवाह से 15 दिन पहले देने, महिला श्रमिकों को 6 महीने के वेतन के बराबर प्रसूति लाभ देने, कार्यस्थल पर बचाव सुरक्षा प्रदान करने, बिना ब्याज के डेढ़ लाख रुपये का कर्ज पंजीकरण के 3 माह के अन्दर देन का नियम बनाने, इसमें 5 साल की शर्त हटाने, साइकिल देने की स्कीम लागू करने, रिहायशी प्लाट देने, लेबर चौकों पर शेड बनाने, पेयजल व शौचालय का इंतजाम करने, मनरेगा में दैनिक मजदूरी 350रुपये करने, स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड बनाने, पंजीकरण शुल्क 1 रुपया मासिक करने की मांग की गई।

मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए भवन निर्माण कारीगर–मजदूर

यूनियन ने झज्जर में श्रम अधिकारी कार्यालय खोलने की भी मांग की। श्रमिक यूनियन के प्रदेश महासचिव कॉमरेड बलराम यादव, उपप्रधान कॉ. धर्मवीर सिंह, जिला प्रधान कॉ. सुन्दर सिंह, जिला सचिव कॉ. जगदीश चन्द्र, राजकुमार पोपा, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के जिला प्रधान कॉ. जिलेसिंह और किसान नेता कॉ. जयकरण दलाल ने श्रमिकों को सम्बोधित किया।

मजदूरों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

नारनौल (हरियाणा) : 10 जनवरी को हरियाणा खेत मजदूर फैडरेशन (सम्बद्धित ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी.) के बैनर तले मजदूरों ने चितवन वाटिका में एकत्रित होकर कॉमरेड सुभाष चन्द के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुँच कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी जरूरतमन्द परिवारों को रिहायशी प्लाट व मकान एवं शौचालय बनाने के लिए ग्राण्ट देने तथा जिन्हें प्लाट अलॉट किए गए हैं उन्हें प्लॉटों पर कब्जा दिलाये जाने, मुफ्त इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाने, मनरेगा की दैनिक मजदूरी का रेट 350 रुपये लागू करने, महंगाई व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, शहर व गाँवों में सस्ते राशन की दुकानें खोलने, गाँव-शहरों के सभी गरीबों को सारा साल काम देने, जिला के प्रत्येक सी.एच.सी. अस्पताल में उचित स्टाफ व दवाइयों का प्रबंध किए जाने आदि की मांग की गई। इस मौके पर कॉ. बलबीर सिंह, कॉमरेड सतीश तथा कॉ. शेरसिंह भी मौजूद थे।

बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में पुतला फूंका

रेवाड़ी (हरियाणा): बिजली दरों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी और शहरों में लगाया गया प्रोपर्टी टैक्स वापस लेने, टोल टैक्स खत्म करने, कृषिभूमि अधिग्रहित न करने, बीमार पशु की मृत्यु पर मुआवजे की मांग पर 13 जनवरी को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) और कृषक खेतमजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय राव तुलाराम पार्क मे इकट्ठा होकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूँका। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व एस.यू.सी.आई. (सी) के जिला सचिव कॉमरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने किया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि बिजली के रेट कम कराने का संघर्ष निजीकरण की नीति के खिलाफ ओत-प्रोत रूप से जुड़ा हुआ है।

ऑल इण्डिया के.के.एम.एस. के जिला सचिव कॉमरेड रामकुमार एवं जिला प्रधान कॉमरेड जय नारायण और श्रमिक नेता कॉमरेड बलराम, कॉमरेड राजबीर आदि ने भी अपने विचार रखे।

आसाम बंध.....

(पृष्ठ 5 का शेष)

कि आसाम के व्यापक सरकुलेशन वाले अखबारों में से एक ने लिखा : ''एकमात्र राजनीतिक पार्टी एसयूसीआई(सी) ने प्रतिवाद में आन्दोलन छेड़ा है जबकि सीपीआई(एम) ने मात्र बयानबाजी करके इतिश्री कर ली है। बाकि पार्टियाँ और संगठन भी मूक दर्शक बने हुए हैं।''(दैनिक असमिया प्रतिदिन 13 दिसम्बर, 2013)

बंध के दिन शाम को पार्टी की राज्य सचिव कॉमरेड चन्द्रलेखा दास ने गर्मजोशी और तत्परता के साथ बंध को भारी सफल बनाने के लिए बधाई दी जिसने विधान परिषद को लोगों द्वारा नकारे जाने को रेखांकित किया है। आन्दोलन और जनसमर्थन ने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया भले ही कुछ हद तक ही सही। इसने एलान किया है कि संसदीय स्थायी कमेटी इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों सहित लोगों की राय जानने के लिए राज्य का दौरा करेगी। पार्टी की राज्य सचिव ने एलान किया है कि जब तक मांग हासिल नहीं हो जाती आन्दोलन जारी रहेगा और तमाम जिलों में और तेज किया जायेगा जहाँ जन अवज्ञा आन्दोलन गठित किया जायेगा जिसका समापन राज्य स्तरीय व्यापक पैमाने पर जन अवज्ञा (सिविल डिसओबिडियेन्स)आन्दोलन में होगा। बंध ने आपसी झगड़ों से जर्जरित आसाम में तमाम तरह की फूटपरस्ती से ऊपर उठ कर मेहनतकश जनता के तमाम तबकों को शामिल कर जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं पर जनवादी आन्दोलन का एक नया अध्याय शुरू किया है।

देश में जन आंदोलन की फिजा तैयार करें – कॉमरेड शिवशंकर

पटना : सीपीआई, सीपीआई(एम) के साथ हमारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) भी आगामी लोक सभा चुनाव में जद(यू) के साथ गठजोड़ कर सकती है इस आशय से संबंधित छपी खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड शिव शंकर ने 12 जनवरी को प्रेस को जारी बयान में कहा कि सीपीआई-सीपीआई (एम) द्वारा जनआंदोलन का रास्ता छोड़कर किसी भी तरह से सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने हेतु दो-चार सांसद और विधायकों के लिए पूंजीवादी-अवसरवादी पार्टियों के साथ सांठगांठ करने के अभ्यास की वजह से देश में वामपंथ कलुषित हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कांग्रेस-भाजपा सहित तमाम सत्ताधारी दलों द्वारा एक के बाद एक जनविरोधी नीतियों के कार्यान्वयन की वजह से उनका जनपक्षीय मुखौटा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और उनका जनविरोधी-पूंजीपतिपरस्त चरित्र उजागर हो गया है, वामपंथ को देश की जनता के सामने एक मुकम्मल विकल्प के तौर पर खड़ा करने तथा देश में जन आंदोलन की फिजा तैयार करने के लिए तमाम वामपंथी दलों को केन्द्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ताकतवर जन आंदोलन निर्मित करने की जरूरत है।

कॉमरेड शिव शंकर ने कहा कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर अन्य वाम दलों के साथ साझे जन सवालों पर संयुक्त आंदोलन की पक्षधर है। साथ ही पार्टी चुनाव के वक्त भी वाम दलों के साथ ही संयुक्त मंच बनाकर आंदोलन की ताकत के तौर पर जनता के बीच जाने की हिमायती है।

साम्राज्यवादी युद्धों का प्रतिरोध करो, जुझारू शान्ति आन्दोलन गठित करो

–लन्दन में आयोजित 'युद्ध नहीं' कांफ्रेंस में कॉमरेड माणिक मुखर्जी

''युद्ध गठजोड़ बन्द करो'' लंदन स्थित साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी संगठन ने 30 नवम्बर 2013 को एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस आयोजित की थी। कान्फ्रेंस की विषयवस्तु थी : 'युद्ध नहीं'। सेण्ट्रल लन्दन में आयोजित इस कान्फ्रेंस में विभिन्न देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांफ्रेंस में शामिल होने और सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित इण्टरनेशनल एण्टी-इम्पीरियलिस्ट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (आईएसीसी) के महासचिव और एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने अपने भाषण में अन्य बातों के अलावा कहा कि मानव इतिहास में एक बहुत ही नाजुक दौर से दुनिया गुजर रही है। भूमण्डलीकरण के नाम पर शासक पूँजीपति वर्ग ने मेहनतकश जनता पर अति घृणित और घातक हमला किया है जिसकी प्रचण्डता का अंदाजा मेहनतकश लोगों के निरन्तर बदतरीन होते जीवन के हालात से लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ 'आतंकवाद का मुकाबला करना' और 'डेमोक्रेसी' के पैरोकार होना साम्राज्यवादियों के लिए दूसरे देशों पर सामरिक आक्रमण चलाने, उनको जबरदस्ती दखल करने और तख्ता पलट का षड्यन्त्र रचने का एक नया बहाना बन गया है। यह 'नई विश्व व्यवस्था' है जिसे अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी थोपना चाहते हैं। इन सब ने संदेहातीत रूप से लेनिन की थीसिस की सच्चाई को सिद्ध किया है कि यह साम्राज्यवाद ही है जो युद्धों को जन्म देता है। बुर्जुआ प्रचार के खोखलेपन का पर्दाफाश हो गया है कि सोवियत खेमे के ढह जाने के साथ ही युद्ध का खतरा और विश्व शान्ति के लिए खतरा समाप्त हो गया है जबकि 1990 से ही साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा युद्ध छेड़े जा रहे हैं। संशोधनवादी नेतृत्व के प्रभाव ने सोवियत यूनियन की ताकत को अन्दर से सोख लिया था; बाहरी अमेरिकी उकसावे के चलते ही अंततः रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रतिक्रान्ति और पूँजीवाद की पुनर्स्थापना हुई थी। विभिन्न देशों की अधिकतर बड़ी-बड़ी स्थापित सोशल डैमोक्रेटिक पार्टियों ने साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ साहसपूर्ण और गैर-समझौतावादी संघर्ष करने के बजाय साम्राज्यवादी तिकड़मों के सामने घुटने टेक दिए और भूमण्डलीकरण की भाषा में बात करने लगी। लेकिन एक-ध्रुवीय विश्व में भी पूँजीवाद में अंतर्निहित द्वन्द्व पूँजीवादी-साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के निरन्तर गहराते संकट का कारण बन रहे हैं। सिकुड़ते हुए विश्व बाजार में हिस्सा पाने की खातिर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच होड़ तीव्रतर होती जा रही है। साम्राज्यवादी ताकतों में से प्रत्येक की विशेषकर अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने की अमेरिकी आधिपत्यवादी आकांक्षा और चाह विश्व को एक असुरक्षित स्थान बना रही है। एक देश को दूसरे देश के खिलाफ या लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काना, राष्ट्र-राष्ट्र और समुदाय-समुदाय के बीच तनाव पैदा करना और उकसाना, युद्ध जैसे हालात पैदा करने और स्थानीय युद्धों का षड्यन्त्र रचना आज दुनिया भर में साम्राज्यवादी कारगुजारियों के निरन्तर लक्षण बन गए हैं। युगोस्लाविया, लेबनान, अफगानिस्तान, ईराक और लीबिया पर किए गए बर्बर मिलिट्री आक्रमणों में और इरान, सीरिया, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, सूडान और लेटिन अमेरिकी देशों पर निरन्तर आर्थिक प्रतिबंध थोपने और उनके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई की धमकी में इसका स्पष्ट प्रकटीकरण हुआ है। इन युद्धों में अति विनाशकारी आयुद्धों के इस्तेमाल, निश्शेषित यूरेनियम बमों के इस्तेमाल, घृणित ड्रोन हमले चलाने, नागरिकों की अंधाधुंध हत्याओं और यातना के भयंकर इस्तेमाल के जरिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों की बर्बरता उजागर हुई है। इसका पूर्वानुमान लगाते हुए कि संशोधनवादी षड्यंत्र के चलते सोवियत यूनियन की अगुवाई वाले सशक्त समाजवादी खेमे के ढह जाने की वजह से अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में विश्व साम्राज्यवादी ताकतें, एक-ध्रुवीय विश्व में बिना किसी अवरोध के अपनी दादागिरी और राहजनी, डाकेजनी और षड्यन्त्रों के साथ आक्रमणकारी और कब्जा करने वाले युद्धों को कई गुना बढ़ा देगी, हमारी पार्टी एसयूसीआई(सी) ने तमाम प्रगतिशील जनवादी सोच रखने वाले साम्राज्यवाद-विरोधी लोगों को चाहे उनके राजनीतिक मत कुछ भी हों, उन्हें शामिल करते हुए युद्ध और साम्राज्यवाद-विरोधी व्यापक आधार वाले पीपल्स फ्रण्टों का निर्माण करने की महत्वपूर्ण जरूरत को महसूस किया जिसमें कम्युनिस्ट एक कोर के रूप में काम करेंगे। जो साम्राज्यवादी आक्रमणों को रोकने का एक प्रभावकारी हथियार होगा। हमारा सुविचारित मत है कि यदि विभिन्न देशों में ऐसे आन्दोलनों को सही तरीके से समन्वित और एकजुट किया जा सके तो एक सशक्त भूमण्डलीय साम्राज्यवाद-विरोधी जुझारू शान्ति आन्दोलन छेड़ा जा सकता है जो प्रभावकारी ढंग से साम्राज्यवादी युद्ध षड्यन्त्रों और तिकड़मों के खिलाफ संघर्ष कर सकेगा। तदनुसार हम उन तमाम पार्टियों के पास गए जो हमारे सम्पर्क में थीं जिनमें इस मामले में अगुवाई करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बेलजियम भी शामिल थी। लेकिन सीपीबी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। इसलिए, इस सम्बन्ध में कुछ अन्य बिरादराना पार्टियों, साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों और ताकतों के साथ बातचीत करके इसके लिए पहल करने की

जिम्मेदारी हम पर आयद हुई। इसके बाद 28-29 नवम्बर 2007 को कलकत्ता में भारी उत्साह और दृढ़निश्चय के बीच सफल साम्राज्यवाद-विरोधी कांफ्रेंस आयोजित की गई। इसमें आईएसीसी का जन्म हुआ, इण्टरनेशनल एक्शन सेण्टर के अध्यक्ष, अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी जनरल और जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता रामसे क्लार्क इसके अध्यक्ष चुने गए। तब से लेकर, अपने ऊपर ली गई जिम्मेदारियों को निभाने के निरन्तर प्रयासों और गतिविधियों के माध्यम से आईएसीसी अति विश्वसनीय और भरोसे लायक संगठन के रूप में उभरा और दुनिया भर में साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों को संचालित और समन्वित कर रहा है। आईएसीसी ने अपनी गतिविधियों को विस्तारित और सुदृढ़ करने के लिए बेरूत और ढाका में दो कान्फ्रेंसें की गई थी। यह जल्द ही उपयुक्त स्थान पर चौथी कान्फ्रेंस की योजना बना रही है। आईएसीसी तमाम साम्राज्यवाद-विरोधी लोगों और ताकतों से साम्राज्यवादी तिकड़मों और साजिशों के खिलाफ जुझारू आन्दोलन गठित करने और साम्राज्यवाद-विरोधी भूमण्डलीय आन्दोलन छेड़ने के लिए इन आन्दोलनों को समन्वित करने के प्रभावकारी तरीके अपनाने की जोरदार अपील करती है जिससे साम्राज्यवादियों के आक्रमणकारी षड्यन्त्रों पर कारगर रोक लगाई जा सकेगी।

'युद्ध नहीं' के आयोजकों ने आईएसीसी के विचार का अनुमोदन किया और संघर्ष में शामिल होने की मंशा जताई। अगले दिन यानी 1 दिसम्बर को कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने आयोजकों के साथ बहुत ही सार्थक मीटिंग की, विचारों और मतों का आदान प्रदान किया और चर्चा की कि किस प्रकार वे आईएसीसी के साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी भूमण्डलीय जुझारू-शान्ति आन्दोलन में सहायता कर सकते हैं।

कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती का भाषण

(पृष्ठ 4 का शेष)

हिन्दी पेपर छोड़ कर किसी ने खबर नहीं दी। इससे आपको समझना चाहिए कि आप अति प्रतिकूल परिवेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। हर प्रगतिशील आन्दोलन को, क्रान्तिकारी आन्दोलन को प्रतिकूल परिवेश के खिलाफ लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। प्रतिक्रियावादी जो पॉवर में हैं वे डरते हैं। वे कभी आपकी मदद नहीं करेंगे बल्कि आपको दबाने के लिए जो कुछ करने का है, वह सब कुछ करेंगे। आप क्या पीछे हट जाओगे? आपको मुकाबला करना होगा। आपका प्रचार और कोई नहीं करेगा वह आपको ही करना है। आपने किया भी है। इस दिल्ली कार्यक्रम से पहले भारत के मुख्य-मुख्य शहरों में जो आपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए उनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और छात्र-नौजवानों ने हिस्सा लिया। आखिरकार दिल्ली में यह सम्मेलन किया और यह प्रतिवाद सभा आपने की है। यह संघर्ष तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही बढ़ेगा। डरने की कोई बात नहीं है। जनता में रोष है, जनता में घृणा है। जनता समाज को बदलना चाहती है। वह रास्ता खोज नहीं पा रही है, रास्ता ढूँढ़ रही है, रास्ता तो आपको ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं रास्ता क्या है। समाजवादी क्रान्ति ही आखिरी रास्ता है। यह यदि आपके मन में गहराई से रहे तो कोई आपको दबा नहीं सकता है। क्रान्तिकारी ताकत, शोषित वर्ग, शोषित-पीड़ित जनता, अत्याचारित जनता जब सचेत हो जाती है, संगठित हो जाती है तब उसको दुनिया की कोई शक्ति कभी दबा नहीं सकी और न दबा सकेगी। अमेरिकी साम्राज्यवादियों की सामरिक शक्ति वियतनाम के पतले-दुबले कमजोर लोगों को दबा नहीं पाई। वियतनाम के क्रान्तिकारी लोगों ने उसको पीट-पीट कर उनकी हड्डी चूर-चूर कर दी थी। उसको वहां से भागना पड़ा था। उत्तरी कोरिया में भी ऐसा ही हुआ। छोटा सा एक द्वीप उस जमाने में 60 लाख की आबादी वाले क्यूबा ने अमेरिका की नाक के नीचे अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए आजादी हासिल की। मार्क्सवादी चिन्तन, मार्क्सवादी आदर्श इतना शक्तिशाली है। वे इसीलिए तो मार्क्सवाद पर इतना हमला करते हैं। मार्क्स की मृत्यु हुई कब 1883 में लेकिन आज भी मार्क्स के नाम से वे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिन्तन इतना शक्तिशाली है। यह आपके पास है।

अतः कॉमरेड्स समस्या गम्भीर है। हो सकता है और भी बहुत कुछ चर्चा होनी चाहिए लेकिन मूल में यही है कि ये नशाखोरी, नशीले पदार्थों का प्रसार और अश्लील विज्ञापन इत्यादि जो आपने देखा कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार और अपराध के कारक हैं। कारक के रूप में वे ठीक हैं लेकिन हो रहा क्यों? हो रहा इसलिए कि बुर्जुआ वर्ग, मालिक वर्ग शोषक वर्ग सर्वहारा क्रान्ति के चिन्तन से डरते हैं और जितना ही यह सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलन चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, इसका विकास होता जाएगा, यह वर्ग और भी डरता जाएगा। सभी के विरोध में आपकी लड़ाई। मैं भरोसा रखता हूँ आप आन्दोलन करके इतना दूर आगे बढ़े हैं आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। आप जीतोगे इतना कह कर आपको क्रान्तिकारी अभिनन्दन देते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ।

इन्कलाब जिन्दाबाद!

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing :20January, 2014

आईटीआई में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के खिलाफ
देश भर में छात्र-नौजवानों के रोष प्रदर्शन

दिल्ली : श्रम मंत्रालय द्वारा आई.टी.आई में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की दिल्ली कमेटी की ओर से 17 जनवरी को दिल्ली के छात्र-नौजवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नौजवानों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शनकारी हाथों में लिखी मांग पट्टिकाएं लिए थे। वे 'आई.टी.आई में सेमेस्टर प्रणाली लागू करना बंद करो', 'आई.टी.आई. छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो', 'छात्र-विरोधी और युवा-विरोधी नीतियों लागू करना बंद करो' आदि नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को संगठन की सचिव कॉमरेड प्रकाश देवी, संगठन के कोषाध्यक्ष इन्द्रदेव, प्रभाष के अलावा एसयूसीआई(सी) की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड हरीश त्यागी ने भी सम्बोधित किया। विरोध सभा का संचालन कॉमरेड इंद्रदेव ने किया।

वक्ताओं ने कहा कि आई.टी.आई के प्राचार्य, ट्रेनरों और अभिभावकों को बगैर कोई पूर्वसूचना दिये और भविष्य में इस ट्रेड से व्यवसाय-रोजगार देने से जुड़े लोगों से बगैर कोई सलाह-मशविरा किए आई.टी.आई में अगस्त 2013 से सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का कदम उठाना देशभर के लाखों विद्यार्थियों के हितों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। इस ट्रेनिंग से संबद्ध विद्यार्थी अक्सर समाज के निम्न आय वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अचानक पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर देगा है। जबकि कोर्स, सिलेबस के प्रारूप में कोई भी परिवर्तन सत्र के शुरू हो जाने के बाद कोर्स की पढ़ाई के दौरान नहीं लाया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत पहले से पर्याप्त समय लेकर संबंधित एक्सपर्टों की राय और रोजगारदाताओं की सलाह लेकर लागू किया जाना चाहिए। मगर इस प्रकार के बदलाव के स्थापित एकेडमिक तौर-तरीके को डीजीईटी व डीईटी दोनों ने तिलांजलि दे दी है।

वक्ताओं ने कहा कि अगर इस सेमेस्टर प्रणाली को तुरंत रद्द नहीं किया गया और आईटीआई ट्रेनिंगों की पूर्ववर्ती स्थिति को छात्र हित में फिर से बहाल नहीं किया गया तो सेमेस्टर पद्धति के खिलाफ कर्नाटक में प्रभावित छात्रों-नौजवानों के चल रहे जोदार संघर्ष की तरह ही दिल्ली के आईटीआई छात्रों के सामने भी सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ संघर्ष तेज करने सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाता।

प्रदर्शन के अंत में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय में रोजगार व प्रशिक्षण के डायरेक्टर जनरल को एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में आई.टी.आई. और आई.टी.सी. कोर्सों से सेमेस्टर प्रणाली पूर्णत: वापस लेने और पहले की तरह लम्बी अवधि के कोर्सों की प्रणाली जारी रखने, ट्रेनिंग के प्रारूप में भविष्य में यदि कोई तब्दीली की जाए तो उसे बृहत्त पैमाने पर सभी रोजगारदाता कम्पनियों और ट्रेडरों से सलाह-मशविरे के (जिसमें चर्चा, बातचीत और विचार-विनिमय के लिए पर्याप्त समय मिले) बाद लागू किये जाने की मांग की गई।

लखनऊ (उ.प्र.) : आई.टी.आई. में सेमेस्टर सिस्टम लागू किये जाने के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की ऑल इण्डिया कमेटी के आह्वान पर 16 जनवरी को अखिल भारतीय स्तर पर विरोध दिवस के मौके पर लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा मार्च किया गया। विधानसभा के सामने आयोजित विरोध सभा का संचालन कॉ. रविशंकर मौर्य ने किया व संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह ने सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सेमेस्टर सिस्टम शिक्षा की सम्पूर्णता के लिये खतरा है। छात्र-शिक्षक सभी प्रवेश परीक्षा व परिणाम मे ही वर्ष भर उलझे रहेगें। छात्रों को प्रैक्टिकल का पर्याप्त मौका नहीं मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि एक ओर विधि निर्माता इण्टरमीडिएट स्तर तक परीक्षा को हटा देना चाहते हैं, वे कहते हैं कि परीक्षा से छात्र तनाव में रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे ही परीक्षा पर परीक्षा (सेमेस्टर, ट्राई सेमेस्टर) ला रहे हैं। आखिर क्यों? यह सब शिक्षा को चौपट कर देगा। फीस दोगुनी-चौगुनी हो जायेगी। यह सब निजीकरण की दिशा में एक कदम है। कॉ. प्रमोद शुक्ल ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर शिक्षण संस्थानों के आधारभूत ढ़ाचे व छात्र-शिक्षक अनुपात आदि को सुदृढ़ करने के बजाय वे सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं। जब वर्ष भर पाठ्यक्रम नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो 6 महीने मे कैसे पूरे होंगे? इससे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा व शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।

सभा को कॉ. इन्द्र कुमार शुक्ल व राजेन्द्र सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सेमेस्टर प्रणाली का विरोध करते हुए आन्दोलन को इसके निर्णायक चरण तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

छात्रा से गैंगरेप...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सचिव अनिल कुमार ने की। सभा में ऑल इंडिया डीएसओ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकर जितेन्द्र ने कहा कि शांभवी के साथ हुए बलात्कार व उसकी निर्मम हत्या ने एक बार फिर से देश को शर्मसार कर दिया है। ऐसी घटनाएँ न हों इसके लिए सरकार का कोई प्रयास नहीं है। उल्टे उच्श्रृंखलता व अपराधी मनोवृत्ति पैदा करने के मकसद से केन्द्र व राज्य सरकारें अश्लील सिनेमा, साहित्य व फिल्मों-धारावाहिकों का प्रचार-प्रसार होने दे रही हैं और बेरोक-टोक शराब बिक्री होने दे रही हैं।

ऑल इंडिया एमएसएस की अनामिका ने कहा कि असल में शासक वर्ग छात्र-युवा शक्ति से भयभीत है। इसलिए वह उनकी नैतिक-सांस्कृतिक रीढ़ को तोड़ देना चाहता है। ऑल इंडिया डीवाईओ के पटना जिला प्रभारी अनिल कुमार चाँद ने कहा कि साल भर गुजर गया केन्द्र सरकार द्वारा गठित जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया।

शांभवी के बलात्कारियों-हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर दृष्टांतमूलक सजा देने, अश्लील सिनेमा-विज्ञापन पर रोक लगाने, शराब के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाने, महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक लगाने की मांग की गई। सभा को ऑल इंडिया डीएसओ के जिला सचिव सरोज कुमार सुमन, सुमन लता मौर्य, पुष्पा कुमारी आदि ने संबोधित किया।

बिजली दर वृद्धि के खिलाफ भिवानी बंध सफल

भिवानी (हरियाणा) : बिजली दर वृद्धि के खिलाफ महापंचायत द्वारा आहूत 10 जनवरी के भिवानी बंध का समर्थन करते हुए इसे सफल बनाने के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह दिनोद गेट पर इकट्ठे होकर शहर में प्रदर्शन किया और नारे लगाए। पार्टी की शहर कमेटी के सचिव कॉमरेड राजकुमार ने कहा कि बिजली दरों मे अनाप-शनाप वृद्धि करके बिजली निगम व हुड्डा सरकार उपभोक्ताओं को लूट रही है। पार्टी ने घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति युनिट की दर पर बिजली देने की माँग की।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) भिवानी जिला सचिव कॉमरेड रामफल ने कहा कि बिजली जन उपयोग की जरूरी सेवा है। इस पर मुनाफा कमाना और बिजली बिलों के साथ तरह-तरह के नामों से नाजायज वसूलियाँ करके उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ लादना सरासर गलत है। कांग्रेस सरकार का यह जनविरोधी कृत्य है। सरकार ने यदि बिजली उपभोक्ताओं की आवाज को नही सुना तो आन्दोलन को पूरे प्रदेश मे फैलाया जाएगा। एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) ने बिजली-पानी के निजीकरण को वापिस लेने और बिजली कम्पनियों की मनमानी शर्तों को खत्म करने की माँग की। पार्टी नेताओं ने भिवानी बंध को पूर्ण सफल करने के लिए भिवानी की जनता को बधाई दी।

भिवानी बंध के दिन इसे पूर्ण सफल बनाने के लिए शहर में प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के कार्यकर्ता

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित। दूरभाष : 011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com